eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

वित्तीय समावेशन, चुनौतियॉं एवं जैम त्रयी की अर्थव्यवस्था में भूमिका – एक समीक्षा

[1]डॉ0 दिनेश कुमार गुप्ता
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर– अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बनबसा, उत्तराखंड

Received: 05 Jan 2021, Accepted: 12 Jan 2021, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2021

Abstract

वित्तीय समावेशन निम्न आय तथा कमजोर समूहों जैसे वर्गों की आवश्यकता वाले उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक, उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया है। विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक करने वित्तीय समावेशन की पहुच के लिये सरकार द्वारा 'डिजिटल भारत' अभियान प्रारंभ किया गया। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही 'जैम त्रयी' (जनधन–आधार–मोबाइल) की आधारशिला रखी गई।

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है।

"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और एलपीजी सब्सिडी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने वित्तीय समावेशन में बैंकिंग सैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका साबित की है।

प्रधानमंत्री ने वित्तीय समावेशन को एक आदत बना लेने की अपील की। उन्होंने बैंकों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से प्रेरणा लेने के लिए कहा। उन्होंने बैंकों से वित्तीय समावेशन के रचनात्मक माध्यम पेश करने की अपील की, ताकि किसानों की आत्महत्या रोकी जा सके।"

मुख्य शब्दावली– वित्तीय समावेशन, जनधन योजना, जैम त्रयी, वित्तीय अपवर्जन, डिजिटल भारत

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, वित्तीय समावेशन निम्न आय तथा कमजोर समूहों जैसे वर्गों की आवश्यकता वाले उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक, उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया है। वर्ष 1980 और 1990 के दशकों में शुरू किये गए ढाँचागत समायोजन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप हुए वित्तीय सुधारों का लाभ अनेक विकासशील देशों को भी मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में बात करें तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में मात्र एक बीमा कंपनी (जो जीवन बीमा एवं कुछ साधारण बीमा योजनाओं का संचालन करती थी) और एक स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत थे। परंतु अब यह दृश्य बदल गया है, वर्तमान में देश में 20 से अधिक बैंक, अनेक बीमा कंपनियाँ तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ–साथ कई प्रकार के वित्तीय संस्थान कार्यरत हैं। वस्तुतः इसका मूल कारण आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप हुआ देश का वित्तीय समावेशी विकास है। हालाँकि, वित्तीय समावेशन के विषय में यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि इसका कार्यक्षेत्र केवल बैंकिंग सेवाओं तक ही सीमित नहीं है, बलकि यह बीमा, इक्विटी उत्पादों और पेंशन उत्पादों आदि विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवाओं के संबंध में भी समान रूप से लागू होता है। स्पष्ट रूप से वित्तीय समावेशन का अर्थ, बैंकिंग सेवा से वंचित किसी भी क्षेत्र में स्थित बैंक शाखा में केवल एक बैंक खाता खोलना मात्र कतई नहीं है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढाँचा होता है। यदि बुनियादी ढाँचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किये जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के एक लिये नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके। वस्तुतः यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके, कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे।

वित्तीय समावेशन की पहुँच बिना किसी रुकावट के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक करने के लिये सरकार द्वारा 'डिजिटल भारत' अभियान प्रारंभ किया गया। भारत को

©IJARMS JOURNAL, 2019

डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ही 'जैम त्रयी' (जनधन–आधार–मोबाइल) की आधारशिला रखी गई। वैश्विक महामारी COVID–19 के दौरान जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुँचने में जैम त्रयी की भूमिका सराहनीय रही है।

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है।

विकासशील देशों के सन्दर्भ में यह पाया गया है कि गरीबी को कम करने में वित्तीय विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव की तुलना में अधिक प्रबल है। जैनी एवं के0 पोद्दार 2011

02–उद्देश्यः–

प्रस्तुत शोधपत्र के उद्देश्य निम्नवत इस प्रकार है–

01– भारत में वित्तीय समावेशन व जैम त्रयी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

02– भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति, सम्भावनाएं व चुनौतियों के बारे में अध्ययन करना।

03– साहित्यिक समीक्षाः–

मवाले (2014)[1] जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अभी भी आर्थिक रूप से बहिष्कृत है और इस तरह जिस कारण गरीबी बढ रही है। अतीत में कई वित्तीय सुधार किए गए हैं लेकिन अंतिम छोर तक लाभ नहीं पहुंचाया जा सका है। प्रधानमन्त्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन की एक योजना है जो विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं से युक्त है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस पर काम करने की आवश्यकता है। (वित्तीय रिपोर्ट 2015)[2] यह रिपोर्ट JAM के तीन घटकों को सामने लाती है। लाभार्थी, लाभार्थी को हस्तांतरण और लाभार्थी तक वितीय सेवाओं की पहुंच प्रदान करना। वित्तीय समावेशन को सफल तथा उत्साहपूर्वक काम करने की क्षमता को मापने के लिए JAM एक सूचकांक है जो अंतिम मील पर खड़े व्यक्ति को बैकिंग की समस्त सुविधाएं प्राप्त हो रही है या

[1] मवाले (एम0वी0) 2014, ए0 स्टडी आफ प्रधानमन्त्री जन–धन–योजना विथ रिस्पेक्ट टू करेन्ट सिचूएशन आफ फाइनेन्सियल इन्क्लूसन इन इंडिया। इन्टरनेशनल रिसर्च जर्नल आफ कामर्स आर्ट एण्ड साइन्स, 41–50

[2] फाइनेन्स, पी0आई0 (2015) स्प्रीडिंग जैम एक्रास इन्डियाज इकानामी।

नही की वस्तुस्थिति को व्यक्त करता है। यह रिपोर्ट PAHAL के तहत किए गए कार्यों को दर्शाती है। जिसने सब्सिडी के रिसाव को 24% कम कर दिया। इस प्रकार पूरे देश में JAM का प्रसार हुआ। (ऐश्वर्या सिंह, 2015)[3] जेएएम को लागू करने में दो पहलुओं पर विचार किया गया है। रिसाव की मात्रा और केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रण। इन्होने अपने अध्ययन के माध्यम से पाया कि पीएमजेडीवाई कमजोर वर्ग और रिकॉर्ड खाते खोलने तक पहुंचने में सफल रही है। इसने अधिकांश गैर बैकिंग क्षेत्रों में अपनी पहुंच को सुनिश्चित किया है।

उपरोक्त साहित्य समीक्षा के आधार पर हम देखते है कि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र अनेक प्रकार के अध्ययन किये गये है। प्रस्तुत शोधपत्र में जैम त्रयी का इस दिशा में क्या योगदान है, पर अध्ययन किया जा रहा है।

04— शोधप्रविधिः—

प्रस्तुत शोध विषय के विश्लेषण हेत वर्णनात्मक शोध—प्रविधि का प्रयोग किया गया है। यह षोध द्वितीयक समंको पर आधारित है। अवधारणा की व्याख्या के लिए द्वितीयक समंक विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों आदि से संग्रहित किए गए है। इसमे परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनो तरह के तथ्यो का प्रयोग किया गया है। उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभिन्न लेखों, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा इन्टरनेट पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया। वित्तीय समावेशन व जैम त्रयी से संबंधित विभिन्न शोध पत्रों का अध्ययन कर विषय को समझने का प्रयास किया गया है।

05— परिणाम व विश्लेषणः—

देश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिये देश के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता का होना आवश्यक है। जबकि देश का एक बड़ा भाग वित्तीय विकास से दूर अपितु अपवर्जित है। वित्तीय अपवर्जन सामाजिक अपवर्जन का भी एक प्रमुख कारण है। एक लक्षित समूह को वित्तीय अपवर्जित कहा जा सकता है जबकि वह मुख्यधारा की औपचारिक वित्तीय सेवाओं जैसे खाता, ऋण, बीमा व भुगतान आदि का लाभ नहीं ले सकता हो। इस समूह में मुख्यतः सीमान्त किसान, भूमिहीन मजदूर या किसान स्वरोजगारी एवं असंगठित क्षेत्र के उद्यमी, शहरी कच्ची बस्तियों के निवासी, प्रवासी जातीय अल्पसंख्यक एवं सामाजिक अपवर्जित समूह व वरिष्ठ नागरिक एवं महिलायें सम्मिलित हैं। इस दिशा में जैम त्रयी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

[3] एसवर्या सिंह, एल0के0, (2015, मार्च), पीएमजेडीवाईः इम्प्रूव्ड फाइनेन्सियल इन्क्लूजन, बट रोडब्लाक्स रिमेन।

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

5.1–वित्तीय समावेशन पहलः– इसके अर्न्तगत जनधन–आधार–मोबाइल के बारे में संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है–

आधार, प्रधानमंत्री जनधन योजना और मोबाइल संचार में वृद्धि ने नागरिकों तक सरकारी सेवाओं के पहुँचने का तरीका बदल दिया है। मार्च 2020 में अनुमान के अनुसार, जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 380 मिलियन से अधिक रही है। व्यक्तिगत पहचान की अवधारणा में महत्त्वपूर्ण बदलाव के साथ आधार न केवल एक सुरक्षित और आसानी से सत्यापन योग्य प्रणाली है, बल्कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में यह एक महत्त्वपूर्ण यन्त्र है। सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश में गरीबों तथा असक्त लोगों को सशक्त बनाने व उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये कई योजनाएँ शुरू की हैं। जिनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड–अप–इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना प्रमुख हैं।

5.2–ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तारः– भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये पहल की है। इनमें प्रमुख हैं–

- इनमें दूरदराज के इलाकों में बैंक शाखाएँ खोलना शामिल है।
- किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।
- बैंकों के साथ स्व–सहायता समूहों का जुड़ाव।
- ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) की संख्या बढ़ाना।
- बैंकिंग क्षेत्र में व्यावसायिक अभिकर्त्ता मॉडल।

5.3–वित्तीय समावेशन का महत्वः–

वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सहित वित्तीय सेवायें पहुँचाने का प्रयास है। इसे 'समावेशी वित्तपोषण' भी कहा जाता है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है।

जनवरी 2015 में 12.55 करोड़ जनधन खातों संचालित थे जो 16 अगस्त, 2017 तक बढ़कर 29.52 करोड़ हो गये। जनवरी, 2015 में ग्र्रामीण क्षेत्र में जहां 7.54 करोड़ जनधन खाते खोले गए थे, वहीं

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

16 अगस्त, 2017 तक उनकी संख्या बढ़कर 17.64 करोड़ हो गई। यही बात रुपे कार्ड पर भी लागू होती है। जनवरी 2015 में जारी हुए 11.08 करोड़ रुपे कार्डों की संख्या 16 अगस्त, 2017 तक बढ़कर 22.71 करोड़ हो गई। लाभार्थियों के खाते की राशि भी बढ़कर 65,844.68 करोड़ रुपये हो गई और प्रति खाता औसत शेष राशि का आंकड़ा भी जनवरी 2015 के 837 रुपये से उछलकर अगस्त, 2017 में 2,231 रुपये हो गया। दूसरी ओर जीरो बैलेंस खातों की संख्या में खासी कमी देखने को मिली है। सितंबर, 2014 में जहां 76.81 प्रतिशत ऐसे खाते थे तो अगस्त 2017 में उनका दायरा सिकुड़कर 21.41 प्रतिशत रह गया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में भी इसने अहम भूमिका निभाई है। मार्च, 2014 तक कुल बचत खातों में 33.69 करोड़ खातों के साथ महिलाओं की 28 फीसद हिस्सेदारी थी। देश के शीर्ष 40 बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी के आंकड़ों के अनुसार इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर तकरीबन 40 प्रतिशत हो गई है। महिलाओं के कुल 43.65 करोड़ खातों में से 14.49 करोड़ खाते जनधन योजना से जुड़े हैं। वित्तीय समावेशन में यह महिलाओं की बडी भूमिका का प्रस्तुत करता है।[4]

- विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस या ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट–2017 के अनुसार, वर्ष 2014 में अनुमानित 53प्रतिशत भारतीय वयस्कों के अपेक्षा वर्तमान में 80 प्रतिशत वयस्कों के पास एक बैंक खाता है।
- जहाँ एक ओर इससे समाज में कमजोर तबके के लोगों को उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिये धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे–बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन उत्पादों आदि में भाग लेकर देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर इससे देश को पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ–साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी संवर्धन प्राप्त होता है।
- पूर्व में निजी वित्तीय संस्थान सीमित आय वाले ग्राहकों के साथ संलग्न नहीं थे, परंतु अब समय बदल गया है, और इस वर्ग के साथ भी निजी वित्तीय संस्थानों (पेटीएम, एयरटेल मनी और जियो मनी जैसे पेमेंट बैंक) की सक्रिय भागीदारी हुई है, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया है कि गरीबों को वित्तीय दायरे में लाना उनके व्यवसाय मॉडल के लिये भी फायदेमंद है।

[4] https://www.india.gov.in/hi/spotlightप्रधानमंत्री–जन–धन–योजना–पीएमजेडीवाय

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

- वितीय सेवाओं का एकीकरण जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का जैम त्रयी योजना के साथ सम्मिलन लाभदायक प्रयोग सिद्ध हुआ।
- वित्तीय समावेशन से सरकार को सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेराफेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे सरकार उत्पादों पर सबसिडी देने के बजाय सबसिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

5.4–चुनौतियाँः– वित्तीय समावेशन व जैम त्रयी के अर्थव्यवस्था में क्रियान्वयन तथा प्रसार के लिए निम्न प्रकार की चुनौतियां दिखायी देती है। जिसका वर्णन इस प्रकार है।

- **सभी की बैंकों तक पहुँच नहीं–** बैंक खाते सभी वित्तीय सेवाओं के लिये एक प्रवेश द्वार हैं। लेकिन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 190 मिलियन वयस्कों के पास बैंक खाता नहीं है, जिससे भारत, चीन के बाद गैर बैंकिंग आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
- **डिजिटल डिवाइड–** कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने के लिये आवश्यक तकनीक का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। इन लोगों में तकनीकी कौशल की भी कमी है।
- **नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन का अभाव–** जन धन योजना के परिणामस्वरूप कई हजार निष्क्रिय खाते खुल गए हैं, जिनमें वास्तविक बैंकिंग लेनदेन कभी नहीं हुआ। ऐसी सभी गतिविधियाँ संस्थानों का खर्च बढ़ती हैं, और विशाल परिचालन लागत संस्थानों की वित्तीय स्थिति के लिये हानिकारक साबित होती हैं। इन विपरीत परिणामों से बचने के लिये, यह महत्त्वपूर्ण है कि सभी हितधारक इस तरह के कार्यक्रमों में उचित उद्देश्य के साथ भाग लें, न कि केवल औपचारिकता के लिये।
- **अनौपचारिक और नकद आधारित अर्थव्यवस्था–** भारत एक नकदी आधारित अर्थव्यवस्था है, जो डिजिटल भुगतान अपनाने की दिशा में एक चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में लगभग 81प्रतिशत व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेनदेन के लिये नकदी आधारित अर्थव्यवस्था पर उच्च निर्भरता के साथ एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का संयोजन डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिये एक बाधा बन गया है।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

- **वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल–** ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट–2017 के अनुसार, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 83 प्रतिशत पुरुषों के अपेक्षा 77 प्रतिशत महिलाओं ने ही किसी वित्तीय संस्थान में खाते का संचालन किया। इस अंतराल के लिये सामाजिक–आर्थिक कारक उत्तरदायी है, जिसमें मोबाइल हैंडसेट की उपलब्धता और इंटरनेट डेटा की सुविधा महिलाओं की तुलना में पुरुषों के बीच अधिक है।

6– निष्कर्षः–

प्रस्तुत शोध पत्र में विश्लेषण के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि भारत में वित्तीय समावेशन की सफलता के लिये, एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिये, जिसके माध्यम से मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन, और नीतिगत ढाँचे को मजबूत किया जाए और नए तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए। यदि मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिये पर्याप्त उपाय किये जाते हैं, तो वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीबों को भी आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त होंगे। **एक अरब + एक अरब + एक अरब विजन–** जनधन, आधार और मोबाइल यानि JAM की 'त्रिमूर्ति' से सामाजिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार की निगाह अब एक अरब–एक अरब–एक अरब पर है। यानि एक अरब आधार नंबर जो एक अरब बैंक खातों और एक अरब मोबाइल फोन से जुड़े हों। इससे सभी भारतीय साझा वित्तीय, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्र में आ चुके हैं। यह कुछ उसी तरीके से है जिससे वस्तु एवं सेवा कर (GST) से एकीकृत बाजार बना है। जनधन, आधार और मोबाइल यानि (JAM)ने देश में फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और डिजिटल क्रांति लाने का काम किया है। अभी तक 52.4 करोड़ आधार, 73.62 करोड़ खाते से जोड़े जा चुके हैं। यह संख्या अब जल्दी ही एक अरब तक पहुंच जाएगी। यानी एक अरब आधार, मोबाइल और अकाउंट्स से जुड़ जाएंगे। जाहिर है मात्र इस कदम से देश के लोग स्वतः फाइनेंशियल और डिजिटल मुख्यधारा का हिस्सा बन जाएंगे।

प्रधानमंत्री जन धन योजना देश के गरीबों के जीवन में नया सवेरा लेकर आया है। इसके माध्यम से न सिर्फ आर्थिक छुआछूत कम हुआ है बल्कि इससे गरीबी हटाने की दिशा में बड़ी सफलता मिल रही है। पहले दिन ही डेढ़ करोड़ खाता खोलने का रिकॉर्ड बना चुकी यह योजना वित्तीय समावेशन की दिशा में केंद्र सरकार की बड़ी पहल है।

सन्दर्भ सूची–

1. रंगराजन, सी., स्टेट्स ऑफ फाइनेन्शियल इनक्लूजन इन इण्डिया 2008, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, 2013
2. स्वदेष सिंह, 'नोटबंदी और डिजिटल लेनदेन से गरीब कल्याण योजना' फरवरी 2017
3. ओकार राय 'सषक्त डिजिटल समाज बनाता भारत' योजना मई 2017
4. सिम्पी चौधरी, 'डिजिटल इंडिया का परिवर्त नकारी प्रभाव' योजना दिसंबर 2018
5. एस वाई कुरैषी, 'विमुद्रीकरण चुनाव पर प्रभाव' योजना फरवरी 2017
6. मनोहरनए पी0 एवं मुथैया के0 फाइनेन्शियल इनक्लूजन इन द इन्डियन रूरल एरिया कन्टेक्स्ट. ए माइक्रो लेवल स्टडीज जे.ए.डी.यू. 2010
7. शर्मा मनीष, (2012)भारतीय परिवारों की बैंकिंग सेवाओं तक कुल पहुँच, राजस्थान पत्रिका मई 2012
8. https://www.india.gov.in/hi/spotlightप्रधानमंत्री–जन–धन–योजना–पीएमजेडीवाय
9. फाइनेन्स, पी0आई0 (2015) स्प्रीडिंग जैम एक्रास इन्डियाज इकानामी।
10. एसवर्या सिंह, एल0के0, (2015, मार्च), पीएमजेडीवाई: इम्प्रूव्ड फाइनेन्सियल इन्क्लूजन, बट रोडब्लाक्स रिमेन।
11. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/financial-inclusion-and-digital-india-a-critical-assessment